भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *33
दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ

विकास कार्यों के लिए डिजिटल भुगतान

*33. श्री वाई.एस.अविनाश रेड्डी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह कदम उठा रही है कि देश की सभी पंचायतें विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग करेंगी और उन्हें 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (यूपीआई) सक्षम पंचायतें घोषित किया जाएगा, यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अट्ठानवें प्रतिशत पंचायतों ने यूपीआई-आधारित भुगतान शुरू कर दिया है और अब पंचायतों को डिजिटल रूप से भुगतान किया जाएगा और चेक और नकद में भुगतान लगभग बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेवा प्रदाताओं और विक्रेताओं के साथ बैठकें आयोजित करने के लिए पंचायतों को 2014 से कोई निर्देश/ परामर्श जारी किए हैं और समुचित सेवा प्रदाताओं को चुनने और विक्रेताओं को अंतिम रूप देने का काम पंचायतों को दे दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पंचायतों को पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले एकल विक्रेता को चुनने का भी निर्देश दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप, मंत्रालय ने पंचायतों के नियोजन, लेखांकन और बजट सहित कार्य को सरल बनाने के लिए एक लेखांकन एप्लीकेशन ई-ग्रामस्वराज लॉन्च किया है। इसके अलावा, खातों के रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि पंचायतें विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर ऑनलाइन भुगतान कर सकें। वर्ष 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश सहित ई-ग्रामस्वराज के तहत की गई प्रगति **अनुबंध-I** में दी गई है। इसके अलावा, मंत्रालय राजस्व संग्रह के लिए पंचायती राज संस्थाओं में यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान विधियों सहित ऑनलाइन भुगतान विधियों को अपनाने के साथ-साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित पंचायतों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क संग्रह के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मामले में, यह राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों को यूपीआई-सक्षम बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त रोलआउट स्थिति को **अनुबंध-II** में देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पंचायतों में यूपीआई आधारित समाधानों की तैनाती के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत भुगतान सेवा प्रदाताओं, भुगतान बैंकों और तृतीय-पक्ष भुगतान एप्लीकेशनों (टीपीएपी) की सेवाओं का उपयोग/लाभ उठाने की सलाह दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से अनुरोध किया गया है कि वह राज्य पंचायती राज विभागों/पंचायतों को उनकी राज्य टीमों के माध्यम से यूपीआई रोलआउट के लिए अपेक्षित तकनीकी/सहायक सहायता प्रदान करे।

***

अनुबंध - I

'विकास कार्यों के लिए डिजिटल भुगतान' के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 33 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या एवं समकक्ष	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	ऑन बोर्ड ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों की कुल संख्या	ऑन बोर्ड जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13296	12907	660	660	639	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	185	0	0	0	25	25	7
3	असम	2662	2197	2170	191	191	185	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8044	534	534	529	38	38	38
5	छत्तीसगढ	11596	11594	11503	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	191	89	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14594	13666	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6225	6221	5829	143	143	131	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3509	81	81	80	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4317	264	264	262	24	24	23
11	कर्नाटक	5954	5954	5935	238	232	117	31	31	28
12	केरल	941	941	940	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23009	22973	313	313	310	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27911	27834	26268	351	351	302	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	120	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1289	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6792	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13222	9173	152	151	110	22	22	19
21	राजस्थान	11211	11206	10739	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	194	0	0	0	6	6	6

23	तमिलनाडु	12525	12525	12518	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12771	12768	12628	540	540	498	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1176	1162	75	75	75	9	9	8
26	उत्तराखंड	7795	7794	7729	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57596	826	826	821	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल		**263481**	**251853**	**241156**	**8658**	**6402**	**6098**	**650**	**642**	**609**

अनुबंध - II

'विकास कार्यों के लिए डिजिटल भुगतान' के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 33 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

यूपीआई रोलआउट: राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक	विक्रेता का चयन	यूपीआई की शुरुआत
1	आंध्र प्रदेश	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• आंध्र प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में UPI आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली शुरू की गई है। 15.08.2023 से UPI और QR-आधारित भुगतान के लिए SBI, UBI, HDFC और IDBI बैंकों को शामिल किया गया है। स्थिति इस प्रकार है। • ग्राम पंचायतों की संख्या:- 13325 • ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ UPI सक्षम है: 13325 • स्थित PoS मशीनों की संख्या: 5032 • पहाड़ी/वन/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कुछ ग्राम पंचायतों में जहाँ सिग्नल/कनेक्टिविटी अभी तक स्थापित नहीं हुई है, राजस्व संग्रह नकद के माध्यम से किया जा रहा है।
2	अरुणाचल प्रदेश	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• यूपीआई सक्षमता के लिए एसबीआई को नियुक्त किया गया • जिला पंचायत को यूपीआई सक्षम बनाया गया है, ग्राम पंचायतों को यूपीआई सक्षम बनाने का कार्य प्रगति पर है
3	असम	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• पंचायतों को संबंधित बैंकों से क्यूआर कोड प्राप्त करने और उन्हें कार्यालयों में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया • असम में 2147 पंचायतें यूपीआई सक्षम हैं
4	बिहार	संचालित	बैंक/सेवा प्रदाता के चयन को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है	
5	छत्तीसगढ	संचालित	बैंक/सेवा प्रदाता	

			चयन को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है	
6	गोवा	संचालित	प्रगति पर है	
7	गुजरात	संचालित	सभी ग्राम पंचायतों में स्थानीय बैंक का क्यूआर कोड लगा होता है।	14181 ग्राम पंचायतों को स्थानीय बैंक द्वारा संचालित क्यूआर कोड से सक्षम किया गया है, जिसे पिछले 6 महीने से ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
8	हरियाणा	संचालित	प्रगति पर है	
9	हिमाचल प्रदेश	संचालित	बैंक/सेवा प्रदाता के चयन को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है	
10	झारखंड	संचालित	बैंक/सेवा प्रदाता के चयन को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है	एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) सक्षम भुगतान अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है
11	कर्नाटक	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• कर्नाटक की सभी ग्राम पंचायतों को पीओएस डिवाइस उपलब्ध कराए गए • कर्नाटक की ग्राम पंचायतों को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत बिलर्स के रूप में शामिल किया गया है। • 100% ग्राम पंचायतों को यूपीआई सक्षम बनाया गया है।
12	केरल	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	100% ने UPI आधारित भुगतान को अपनाया है
13	मध्य प्रदेश	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• सभी ग्राम पंचायतों को यूपीआई सक्षम बनाया गया है। नागरिकों से कर/शुल्क प्राप्त करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का क्यूआर/वीपीए सार्वजनिक डोमेन में अपलोड किया गया है। • सभी ऑनलाइन भुगतान साधनों के लिए एनएसडीएल के सहयोग से एमपीएसईडीसी द्वारा विकसित यूनीपे को लागू करने के अंतिम चरण में है । • सभी ग्राम पंचायतों को नकद या चेक न लेने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
14	महाराष्ट्र	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• 22509 ग्राम पंचायतों को यूपीआई सक्षम बनाया गया है।
15	मणिपुर			
16	मेघालय			
17	मिजोरम	संचालित	सेवा प्रदाता के चयन	शून्य

			को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है	
18	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
19	ओडिशा	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	पंचायतें UPI के माध्यम से स्व-केंद्रित राजस्व (OSR) एकत्र कर रही हैं।
20	पंजाब	संचालित	सेवा प्रदाता के चयन को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है	
21	राजस्थान	संचालित	सेवा प्रदाता के चयन को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है	
22	सिक्किम	संचालित	स्थानीय बैंकों को यूपीआई सक्षमता के लिए सूचित कर दिया गया है	• 100% पूर्ण
23	तमिलनाडु	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• तमिलनाडु में सभी ग्राम पंचायतों का कर संग्रह ऑनलाइन भुगतान विधियों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और पीओएस मशीनें शामिल हैं।
24	तेलंगाना	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• राज्य एप्लीकेशन पहले से ही UPI आधारित भुगतान की अनुमति देता है
25	त्रिपुरा	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• सभी ग्रामीण स्थानीय निकाय यूपीआई सक्षम हैं
26	उत्तराखंड	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• सभी पंचायतें UPI सक्षम हैं
27	उत्तर प्रदेश	संचालित	विक्रेता चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।	• सभी पंचायतें डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए यूपीआई सक्षम हैं।
28	पश्चिम बंगाल	संचालित	फोनपे को यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली के लिए सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया है।	• आज तक 3339 ग्राम पंचायतों में से 259 ग्राम पंचायतें यूपीआई सक्षम हैं।
29	जम्मू और कश्मीर	संचालित	प्रगति पर है	
30	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य

***